

FREE EBOOK



अटल मिशन

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन



For SSC, Railway, State Govt Exams

अटल मिशन

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या “अमृत” शहरों में हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक परियोजना है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का नया नाम है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नाम बदलकर अमृत (AMRUT) कर दिया गया था। परियोजना के तहत सभी कार्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत हरदीप सिंह पुरी मंत्री हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा सचिव हैं, थारा डी संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक हैं, विनय प्रताप निदेशक हैं, राजकुमार और सुनीत मेहता उप सचिव हैं, राजेश कुमार, राजीव कुमार दास और एचसी प्रसाद सचिव हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेहतर जलापूर्ति सुविधाएं और पानी तक पर्याप्त पहुंच, अच्छी गुणवत्ता वाले सीवरेज सुविधाएं, अच्छा वातावरण और अच्छे माहौल के लिए खुले स्थान प्रदान करके बड़ी जल निकासी नालियां बनाना है ताकि बाढ़ का पानी आराम से उन नालियों के जरिए निकल सके और सभी को एक बेहतर जीवन शैली भी प्रदान करना है। सरकार ने इस मिशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

सेवा स्तर सुधार योजना (SLIP)

सेवा स्तर सुधार योजना या “SLIP” को शहर स्तर पर सेवाओं और सुविधाओं में सुधार के लिए एक योजना या विचार के रूप में माना जा सकता है। इन योजनाओं का उद्देश्य जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी आदि की मौजूदा प्रणालियों में सुधार करना है।

राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP)

राज्य वार्षिक कार्य योजना या “SAAP” सभी शहर-स्तरीय योजनाओं का एक संयोजन है। या अपने राज्यों में अमृत मिशन के तहत सभी शहरों के लिए “SLIP” योजना है। ये योजनाएं हर घर में सालाना आधार पर जलापूर्ति और सीवरेज पर सिस्टम या बुनियादी ढांचे में किए गए सुधारों को दर्शाती हैं।

विकास के लिए लक्षित क्षेत्र

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर घर में चौबीसों घंटे पानी हो और सीवरेज की उचित सुविधा भी हो इसके साथ-साथ सरकार पार्कों का निर्माण और हरियाली में वृद्धि और प्रदूषण को कम करके पर्यावरण में सुधार करना चाहती है। इसका उद्देश्य मौसम की रिपोर्ट के लिए बेहतर गैजेट प्रदान करना और अधिकांश लोगों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना भी है। सरकार का लक्ष्य पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और साइकिल चालकों के लिए सड़क मार्ग प्रदान करके परिवहन सुविधाओं में सुधार करना है।

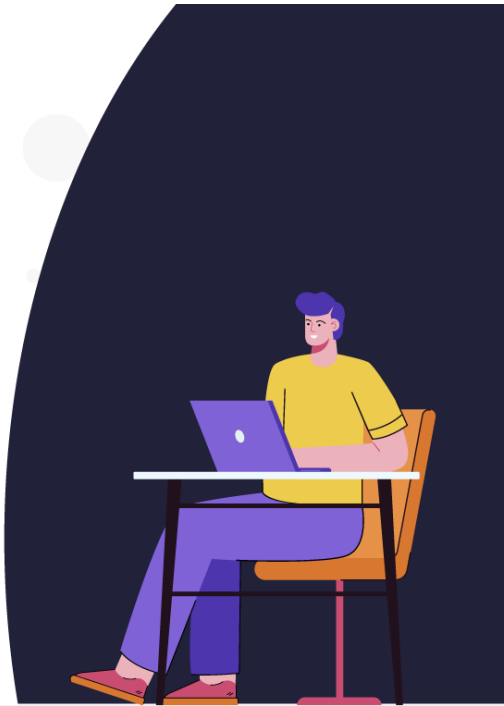
जलापूर्ति

इसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति की बुनियादी व्यवस्था में सुधार करना है ताकि शहर के हर घर में पीने के पानी की आपूर्ति की जा सके। इस योजना के तहत निम्न कार्य किए जा रहे हैं जैसे –मौजूदा जल निकायों और भूजल को पुनर्भरण करना, व्यवस्था करना ताकि अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया जा सके, पुरानी जल आपूर्ति प्रणालियों की वर्तमान प्रणालियों में सुधार करना है। सरकार इस मिशन के तहत शहरों के 100% घरों को कवर करना चाहती है। अब तक 22.89 लाख कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। 77,460 करोड़ रुपये एसएएपी के लिए आवंटित कुल राशि है, 39,011 रुपये, जो कुल राशि का लगभग 50% है, पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए आवंटित या रिजर्व किया गया है और यह मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।



All-India Live Test For

**SSC CGL
TIER-2 |
RRB NTPC
CBT-2**



Gauge your prep-level before you appear for
SSC CGL Tier-2 or RRB NTPC CBT-2 exam. Attempt
All-India Live MockTest to know your current standing,
strengths, and which topics to focus your prep on!



Attempt Latest Pattern
Test in Hindi/English



Detailed Solution +
Performance Analysis

SSC CGL Tier-2

Quantitative Ability &
English

View Details

RRB NTPC CBT-2

Gen. Intelligence & Reasoning
| Maths | Gen. Awareness

View Details

Sign In ➔ Attempt Test ➔ Analyze Performance

सीवरेज और सेप्टेज

इसका उद्देश्य सीवरेज और सेप्टेज प्रशासन की बुनियादी प्रणाली को उन्नत करना और सिस्टम की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अधिकतम संख्या में घरों को कवर किया जाए। शहरों में 62% घरों को प्रबंधक निकाय द्वारा लक्षित किया जाता है, जो कि कवर किए गए परिवारों के वर्तमान प्रतिशत से दोगुना है। जिन परियोजनाओं को पूर्ण करने की योजना है, वे हैं परस्पर भूमिगत प्रणालियों का निर्माण, सीवरेज उपचार संयंत्र, मौजूदा प्रणालियों की स्थिति को बहाल करना और सीवरों की सफाई करना। 77,460 करोड़ रुपये, जो सभी एसएएपी के लिए आवंटित कुल राशि है, 32,456 रुपये, जो कुल राशि का लगभग 42% है, सीवरेज प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के लिए आवंटित या रिजर्व है। यह मिशन प्राथमिकता के मामले में दूसरे नंबर पर है।

स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज

इसका उद्देश्य स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज के लिए बुनियादी ढांचे का विकास या निर्माण करना है ताकि बाढ़ आने पर भारी नुकसान से बचा जा सके। योजना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बाढ़, साथ ही साथ जल-जमाव की समस्याएं कम हो जाएं और अंततः पूरी तरह से बंद हो जाएं। इस खंड या परियोजनाओं के हिस्से में वृद्धि के लिए योजना बनाई गई है जिसमें नालियों के उचित नेटवर्क की स्थापना करना, मौजूदा नदियों या जल निकासी नहरों की मरम्मत करना, फिल्टर की स्थापना करना आदि शामिल है। 77,460 करोड़ रुपये एसएएपी के लिए आवंटित कुल राशि है, 2,969 रुपये, जो कुल राशि का लगभग 4% है और ये स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आवंटित या रिजर्व है। जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था के बाद इस मिशन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

परिवहन सुविधाएं

इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना और गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाएं प्रदान करना और सभी के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करना है। इस योजना का कार्य बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और खेल के मैदानों का निर्माण करना और फुटपाथ, फुट ओवर ब्रिज आदि का निर्माण करना है। 77,460 करोड़ रुपये, जो सभी एसएएपी के लिए आवंटित कुल राशि है, 1,436 रुपये, जो कुल आवंटित राशि का लगभग 2% है, यह गैर-मोटर चालित परिवहन के लिए आवंटित या रिजर्व है, और 1768 रुपये, जो पार्कों और हरियाली के लिए आवंटित किया गया है जो की आवंटित राशि का लगभग 2% है। अन्य मिशनों की तुलना में इस मिशन की प्राथमिकता कम है।

SAAP के अनुसार आवंटित निधियों का राज्य-वार वितरण नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	राज्य	SAAP
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	10.82
2	आंध्र प्रदेश	2890.17
3	अरुणाचल प्रदेश	140.25
4	असम	657.14
5	बिहार	2469.77
6	चंडीगढ़	95.07

7	छत्तीसगढ़	2192.76
8	दादरा और नगर हवेली	10.82
9	दमन और दीव	18.03
10	दिल्ली	802.31
11	गोवा	209.18
12	गुजरात	4884.42
13	हरियाणा	2565.74
14	हिमाचल प्रदेश	304.52
15	जम्मू और कश्मीर	593.05
16	झारखंड	1245.74
17	कर्नाटक	4952.87
18	केरल	2357.18
19	लक्षद्वीप	3.61
20	मध्य प्रदेश	6200.67
21	महाराष्ट्र	7759.32
22	मणिपुर	180.31
23	मेघालय	80.14
24	मिजोरम	140.25

25	नागालैंड	120.22
26	ओडिशा	1598.96
27	पुडुचेरी	64.91
28	पंजाब	2766.62
29	राजस्थान	3223.94
30	सिक्किम	40.06
31	तमिलनाडु	11194.78
32	तेलंगाना	1666.26
33	त्रिपुरा	148.25
34	उत्तर प्रदेश	11421.67
35	उत्तराखंड	593.02
36	पश्चिम बंगाल	4035
	कुल	77640.02

हमें उम्मीद है कि इस लेख ने आपको अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) से सम्बंधित सभी जानकारी आपको पसंद आयी होगी ।
किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, ओलिवबोर्ड पर हमसे संपर्क करें।

FREE Ebooks

[Download Now](#)

Current Affairs

[Explore Now](#)

FREE MOCK TESTS + TOPIC TESTS + SECTIONAL TESTS

For Banking, Insurance, SSC & Railways Exams

[Web](#)

[APP](#)

BLOG

Your one-stop destination
for all exam related
information & preparation
resources.

[Explore Now](#)

FORUM

Interact with peers & experts,
exchange scores
& improve your preparation.

[Explore Now](#)



www.OliveBoard.in